सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है । लेकिन बाढ़ नियंत्रण, जल-निकास और नदी-कटाव संबंधी ऐसी सभी स्कीमें, जिनकी अनुमानित लागत 50 लाख रुपये से अधिक हो, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को मंजूरी और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) भारत सरकार द्वारा स्थापित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने राज्य सरकार की सहायता से घाघरा उप-बेसिन के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है । उनके द्वारा राप्ती के उप-बेसिन की मास्टर योजना अभी प्रस्तुत की जानी है ।

Reserve Quota of Accommodation of S.C. and S.T.

3479. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the justification of Government in reserving accommodation in type III and IV to Scheduled Castes and Tribes together to 5 per cent only instead of 22.5 per cent as provided in recruitment rules;

(b) will the Government rectify this injustice with the Scheduled Castes/Tribes ignoring their quota consideration and social attitude towards them;

(c) is there any proposal to extend the reservation in allotment for S.C./S.T. in type V and above Government accommodation; and

(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). 5 per cent of the clear vacancies in types III and IV in general pool in Delhi/New Delhi are reserved for SC and ST employees. This percentage was fixed after examining the number of such officers who are in occupation of Government accommodation and who are without Government accommodation vis-a-vis the other employees. SC and ST employees are also eligible for allotment in their own turn from the general quota.

(c) No, Sir.

(d) From the information collected about the number of SC & ST officers, who are entitled to type V and above accommodation from general pool in Delhi/New Delhi, it was considered that no reservation is necessary for them, keeping in view the existing level of satisfaction.

Discontinuance of Priority Allotment of Flats to Indians abroad by DDA against Foreign Exchange

3480. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority has decided to discontinue schemes by which Indians abroad were getting priority allotment of flats on payment of cost in foreign exchange; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The response was not significant.

देश में गृह विहीन व्यक्तियों के लिये मकान

3481. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास अपने स्वयं के मकान नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन परिवारों की आवास की समस्या को हल करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह समस्या कब तक हल हो जाने की संभावना है और इस पर कितना धन खर्च होगा ; और

(ग) इस समस्या को हल करने में सरकार को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को देश में मकानों की अनुमानित कमी 156 लाख एकक थी—38 लाख नगरीय क्षेत्रों में और 118 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में ।

(ख) और (ग). आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) ऐसे आवासीय कार्यक्रम को अपनाना जिस का उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पिछले वर्षों की आवास की कमी पूरी करना और जन संख्या की वृद्धि के कारण हुई मकानों की अतिरिक्त मांग पूरा करना तथा बेकार मकानों के स्थान पर नये मकान बनाना है ।

(ii) सरकारी निधियों को निम्न आय के परिवारों के लिए नियन्त्रण करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गए साधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके ।

(iii) बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ।

यदि नगरीय क्षेत्रों में एक मकान का औसत मूल्य 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,000 रुपये लगाया जाए तो मकानों पर प्रतिवर्ष लगाने के लिए कुल पूंजी 2,640 करोड़ रुपये बनती है ।

आपात स्थिति के दौरान पटपड़गंज क्षेत्र से परिवारों को हटा कर उन्हें खिचड़ीपुर जे०जे० कालोनी बसाया जाना

3482. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र के कितने परिवारों को खिचड़ीपुर जे० जे० कालोनी में बसाया गया है ;

(ख) उनके बयानों के अनुसार उनमें से कितने परिवार उनकी जगहों पर या उनके समीप वापिस भेज दिये गये हैं तथा प्रत्येक परिवार को कितनी जमीन दी गयी है अथवा देने का विचार है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण जनरल पावर आफ अटार्नी के प्रमाणों को नहीं मनाता और भूमि के रिकार्ड में मालिक के नामों के दाखिल खारिज प्रमाण-पत्र सहित बिक्रय विलख पर जोर देता है ; और

(घ) यदि हां, तो इन परिवारों को उनके स्थानों पर पुनः कैसे और कब तक बसाया जायेगा और इस संबंध में क्या तरीका होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Percentage of Total Area under Irrigation in Andaman and Nicobar Islands

3483. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the percentage of the total agricultural area in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands which has been brought under irrigation so far; and

(b) whether there are any schemes to provide more irrigation facilities for the farmers there, if so, details thereof?